(b) the details of amounts of money proposed to be spent by the Central Government during the forthcoming Eighth Five Year Plan period, town-wise details for all the States of north-eastern region for their development?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) (a) The details of funds released under the two Centrally Sponsored schemes of Integrated Development of Small and Medium Towns & Urban Basic Services are given in the Annexures [*See* Appendix CXLIX, Annexure Nos. 98 and 99 respectively]

(b) Towns under the Scheme of IDSMT are allocated on Plan to Plan basis. The release of Central assistance to various States would depend on various factors like (i) 8th Plan over-all allocations; (ii) State-wise allocaton of towns, (iii) progress of implementation achieved by the State from time to time, etc.

उड़ीसा में विकलांग व्यक्तियों और आदिवासियों के लिए रोज़गार

1740 **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की सभी राज्यो, विशेषकर उडीसा में विकलाग व्यक्तियों और आदिवासियो को रोज़गार कार्यालयो में नाम दर्ज कराये जाने के दो-दो वर्षों के बाद भी रोज़गार प्रदान नहीं किया जाता जबकि इन व्यक्तियो को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए,

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं और

(ग) यदि नहीं तो क्या इस बारे में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय मे उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा कृष्ण मालवीय: (क) और (ख) रोज़गार कार्यालयो में पजीकृत रोज़गार चाहने वाले व्यक्तियों, जिनमें विकलांग तथा आदिवासी वयक्ति सम्मिलित हैं, की नियुक्ति उनके लिए अधिसूचित रिक्तियों पर निर्भर करती है। अधिसूचित रिक्तियों तथा रोजगार कार्यालयों में पजीकृत उम्मीदवारों में बहुत अधिक अंतर होने के कारण, कुछ प्रतीक्षा अवधि होने की सम्भावना है जो अलग-अलग राज्यों तथा व्यवसायों के अनुसार भिन्न होती है। तदनुसार, उड़ीसा तथा कई अन्य राज्यो में, विकलांग तथा आदिवासी उम्मीदवारो के लिए भी प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक है। तथापि, विकलाग तथा आदिवासी उम्मीदवारों को व्यवसायों की विभिन्न श्रेणियों में उनके लिए आरक्षित कोटा का लाभ मिलता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Khus khus plantation for soil and moisture conservation

1741. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the World Bank experts advocate the Khus-khus or vativer grass planting as a vegetative method of soil and moisture conservation;

(b) whether the suitability and usefulness of this plant for soil conservation has been demonstrated in World Bank aided projects in Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra and Madhya Pradesh;

(c) if so, the results thereof; and

(d) if the resutls are encouraging what are the reasons for not popularising this practice?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) The khus or vativer grass is being used for soil and moisture conservation as hedge plant in many parts of the country from time immemorial. The World Bank experts only located it and gave impetus for the propagation of this technology in a larger area

(b) On preliminary observation, the khus or vativer is found to be useful